GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

RAJYA SABHA
STARRED QUESTION NO. 229

TO BE ANSWERED ON 17th MARCH, 2021

Oil and gas infrastructure

229 Shri B. Lingaiah Yadav:

Will the Minister of ***Petroleum and Natural Gas*** be pleased to state:

(a) whether Government is working to reduce import dependence and proposes to increase the share of renewable sources in the energy basket to 40 per cent by year 2030 and to work towards clean and green sources of energy and reduce energy dependence and increasing focus on clean and green energy sources and ethanol, and planning to spend around Rs 7.5 trillion in creating oil and gas infrastructure over five years; and

(b) if so, the details and the present status thereof, as on date?

ANSWER

MINISTER OF PETROLEUM AND NATURAL GAS
(SHRI DHARMENDRA PRADHAN)

(a) & (b): A statement is laid on the Table of the House.

Statement referred to in reply to parts (a) to (b) of Rajya Sabha Starred Question No. 229 asked by Shri B. Lingaiah Yadav to be answered on 17th March, 2021 regarding "Oil and gas infrastructure".

(a) & (b): Indian Energy Basket has a predominant share of Coal, followed by Oil, Natural Gas and Renewables etc. Government is working to reduce import dependence and has taken multiple steps towards green and clean sources of energy like promotion of renewables and alternate fuels like ethanol, second generation ethanol, compressed bio gas and biodiesel, which are being given high priority in the energy mix and will help in reducing country's import dependence. The National Biofuel policy of 2018 also focuses on giving impetus to advanced biofuels. Other initiatives include promotion of natural gas as clean fuel/feedstock in the country with a view to move towards a gas based economy, refinery process improvements, promoting energy efficiency and conservation, efforts for increasing production of oil and natural gas through various policies under Production Sharing Contract (PSC) regime, Discovered Small Field Policy, Hydrocarbon Exploration and Licensing Policy, Setting up of National Data Repository, etc.

Ethanol blending in Petrol by Oil Marketing Companies has increased from 38 crore litres in Ethanol Supply Year (ESY) 2013-14 to 173 crore litres in ESY 2019-20. Under the plan for setting up Compressed Bio Gas under SATAT initiative, 871 LoIs have been issued till date. After completion of 10th round City Gas Distribution bidding, CGD would be available in 232 geographical areas comprising 407 districts spread over 27 States and Union Territories covering approximately 70 percent of India's population and 53 percent of its geographical spread. As on February 2021, 92.97 GW of renewable energy capacity (excluding large hydro) has been installed in the country.

As a part of its Nationally Determined Contributions under the Paris Agreement on Climate Change, India has committed to achieve at least forty percent of its total electricity generation capacity from non-fossil fuel sources by 2030. The share of renewable energy (excluding large hydro) in the total installed capacity is already about 24.5 percent.

Development of India's energy infrastructure will involve huge investments in oil and gas infrastructure of more than Rs 7.50 trillion including in exploration and production of oil & gas, oil refining, pipelines, city gas distribution networks and LNG terminals. Important sectors having thousands of crores of investment potential include, upstream oil and gas exploration and production, gas pipelines infrastructure for connecting national gas grid, city gas distribution networks in the newly authorized geographical areas, LNG terminals, compressed bio-gas plants, capacity addition of refineries, fertilizer plants and petro-chemical parks and ancillary industries and CNG auto sector.

x-x-x-x-x

भारत सरकार

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

राज्य सभा

तारांकित प्रश्न सं0 229

दिनांक 17 **मार्च**, 2021

तेल और गैस अवसंरचना

229. **श्री बी लिंग्याह यादव**:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार आयात निर्भरता को कम करने और वर्ष 2030 तक ऊर्जा क्षेत्र में नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को 40 प्रतिशत तक बढ़ाने के लिए कार्य कर रही है तथा ऊर्जा के स्वच्छ और हरित स्रोतों की दिशा में और ऊर्जा पर निर्भरता कम करने और ऊर्जा के स्वच्छ और हरित ऊर्जा एवं एथनॉल पर अधिक ध्यान केन्द्रित करने और पांच वर्षों के दौरान तेल और गैस अवसंरचना सृजित करने के लिए करीब 7.5 ट्रिलियन रुपए खर्च करने की योजना बनाने का कार्य कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो आज की तिथि के अनुसार इस संबंध में ब्यौरा और वर्तमान स्थिति क्या है?

उत्तर

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री

(**श्री धर्मेन्द्र प्रधान**)

(**क**) **और** (**ख**): एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

''तेल और गैस अवसंरचना'' के संबंध में संसद सदस्य श्री श्री बी लिंग्याह यादव द्वारा पूछे गए दिनांक 17.03.2021 **के राज्य सभा तारांकित प्रश्न सं**. 229 **के भाग** (**क**) **और** (**ख**) **के उत्तर में उल्लिखित विवरण।**

(क) और (ख): भारतीय ऊर्जा बॉस्केट में कोयले का एक प्रमुख हिस्सा है और इसके बाद तेल, प्राकृतिक गैस तथा नवीकरणीय ईंधन आदि आते हैं। सरकार आयात निर्भरता को कम करने के लिए काम कर रही है और ऊर्जा के हरित और स्वच्छ स्रोतों के संबंध में कई कदम उठाए हैं जैसे नवीकरणीय ईंधनों तथा वैकल्पिक ईंधनों जैसे एथेनॉल, दूसरी पीढ़ी एथेनॉल, संपीडित प्राकृतिक गैस तथा जैव डीजल को बढ़ावा देना, जिन्हें ऊर्जा मिश्रण में उच्च प्राथमिकता दी जा रही है और इससे देश की आयात निर्भरता को कम करने में मदद मिलेगी। राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति, 2018 का लक्ष्य भी विकसित जैव ईंधनों को बढ़ावा देना है। अन्य पहलों में एक गैस आधारित अर्थव्यवस्था की दिशा में आगे बढ़ने के उद्देश्य से देश में स्वच्छ ईंधन/फीडस्टॉक के तौर पर प्राकृतिक गैस को बढ़ावा देना, रिफाइनरी प्रोसेस में सुधार, ऊर्जा दक्षता और संरक्षण को बढ़ावा, उत्पादन हिस्सेदारी संविदा (पीएससी) व्यवस्था के तहत विभिन्न नीतियों के माध्यम से तेल और प्राकृतिक गैस का उत्पादन बढ़ाने के प्रयास करना, खोजे गए लघु क्षेत्र नीति, हाइड्रोकार्बन अन्वेषण और लाइसेंसिंग नीति, नेशनल डैटा रिपोजटिरी आदि की स्थापना करना शामिल हैं।

तेल विपणन कंम नियों द्वारा पेट्रोल में एथेनॉल मिश्रण की मात्रा एथेनॉल आपूर्ति वर्ष (ईएसवाई) 2013-14 के 38 करोड़ लीटर से बढ़कर ईएसवाई 2019-20 में 173 करोड़ लीटर हो गई है। सतत पहल के तहत संपीडित जैव गैस संयंत्र की स्थापना करने की योजना के तहत, आज की तारीख तक 871 आशय-पत्र (एलओआईज) जारी किए गए हैं। नगर गैस वितरण बोली का 10वां दौर पूरा होने के बाद, 27 रा यों और केन्द्र शासित प्रदेशों की लगभग 70 प्रतिशत भारतीय आबादी तथा 53 प्रतिशत इसके भौगोलिक फैलाव को कवर करते हुए 407 जिलों के 232 भौगोलिक क्षेत्रों में सीजीडी उपलब्ध होगी। फरवरी, 2021 की स्थिति के अनुसार, देश में 92.97 जीडब्ल्यू नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता (बड़े हाइड्रो संयंत्रों को छोड़कर) स्थापित की गई है।

जलवायु परिवर्तन पर किए गए पेरिस समझौता के तहत राष्ट्रीय तौर पर निर्धारित अंशदानो के एक भाग के रूप में, भारत वर्ष 2030 तक गैर-जीवश्म स्रोतों से अपनी कुल बिजली उत्पादन क्षमता के कम से कम चालीस प्रतिशत का लक्ष्य हासिल करने के लिए प्रतिब है। संस्थापित कुल क्षमता में नवीकरणीय ऊर्जा का हिस्सा (बड़े हाइड्रो संयंत्रों को छोड़कर) पहले से ही लगभग 24.5 प्रतिशत है।

भारत की ऊर्जा बुनियादी सुविधाओं के विकास कार्य में तेल और गैस क्षेत्र में अन्वेषण और उत्पादन, तेल शोधन, पाइपालइनों, नगर गैस वितरण नेटवर्कों तथा एलएनजी टर्मिनलों सहित तेल और गैस बुनियादी सुविधाओं पर किया जाने वाला 7.50 ट्रिलियन रुपए से अधिक का भारी निवेश शामिल होगा। जिन महत्वपूर्ण क्षेत्रों में कई हजार करोड़ के निवेश की संभावना है उमें अपस्ट्रीम तेल और गैस अन्वेषण और उत्पादन, राष्ट्रीय गैस ि ड से जोड़ने के लिए गैस पाइपलाइन बुनियादी सुविधाएं, नए प्राधिकृत भौगोलिक क्षेत्रों में नगर गैस वितरण नेटवर्क, एलएनजी टर्मिनल, संपीडित जैव-गैस संयंत्र, रिफाइनरियों का क्षमता विस्तार, उर्वरक संयंत्र तथा पेट्रो-रसायन पार्क तथा सहायक उद्योग और सीएनजी ऑटो क्षेत्र शामिल हैं।

*****